[Shri B. R. Bhagat]

withdrawal of these big powers from the region.

Shri Masani again referred to the Council of Asia, a theory which was propounded by the former foreign Minister, Shri Chagla, and asked what we were doing about it. He charged us that having developed this theory we are just sitting idle. This is not a fact. This again goes to our approach to the question. The basis of our approach is co-operation of the people of Asia. What we want is a broadbased economic organisation of all countries in Asia so that no single country or group of countries from Asia or outside can dominate any country in Asia. We do not want such an organisation to have any political undertones or military overtones, for that would only divide Asia into conflicting groups and make them the camp followers and satellites of bigger powers. At the same time, we do not wish to gatecrash into any regional organisation that may be there.

Very soon the ministers of some of the countries of the South and South East Asian region are meeting in Singapore and if a consensus emerges that India should also send an observer, we will send our observer there only to demonstrate that in any effort of closer economic organisation and coming together in a friendly and peaceful manner to solve the basic problems of this region we will play our part. In the whole concept of this Council of Asia this fact remains.

Therefore, by taking these instances I only say that the basic policies of reciprocal friendship, friendly co-operation with other countries and each country depending on its own right to free decision based on co-existence and non-alignment—all these policies are the basic policies of our foreign relations—stand vindicated in the changing world. Those who raised fingers and doubted all these policies have been proved wrong; history has proved them wrong. These policies have stood us well and based on these we are trying to implement this policy. Today our relations with our neighbouring countries are closer. They understand us better. I think, if we pursue this policy, the day will not be far off when we will be able to create a viable area, free from conflict and free from any political or military pressures, which will be viable economically and politically. I think, to describe our foriegn policy either as shambles or a failure, as I said, to say the least, is a subjective remark and it is not in the national interest to say that because, basically, our policy is that we are going forward in our attempt of projecting our correct image and of foreign new links in our foreign relations. There may be some dark areas, there may be areas where we may not have succeeded. But to completely brush it with tar, I think, is not fair. Therefore, I state again that we have followed the right policies and that the policies are paying dividends and it is in our national interest that we pursue these policies.

---

17 hrs.

DISCUSSION ON STATEMENT BY HOME MINISTER RE. INCIDENTS RELATING TO HARIJANS

MR. SPEAKER: We now take up discussion under Rule 193 regarding certain incidents relating to Harijans. Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Sir, last time, I had mentioned regarding the motion which was already before the House regarding the atrocities committed on the Harijans of Madhya Pradesh. You were kind enough to say that it would be taken up in the House. . . . .

MR. SPEAKER: I will give you a chance. We will conclude the other

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli): I had given notice. . . .

MR. SPEAKER: It depends on your Party. I have no objection. There is

one thing I would like to say. At 7 O' Clock we have to adjourn because the President is coming there. So, we tion in the Central Hall. It will not be proper for us to sit here when the President is coming there. So, we have got exactly two hours. If there are long speeches, it will be at the cost of others.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I will take only 15 minutes.

MR. SPEAKER: Yes.

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय माननीय गृह-मंत्री महोदय ने आंध्र प्रदेश के अन्दर जो कांड 28 मार्च को हुआ उसके बाद जो विवरण दिया है और उसके बाद यू० पी० में जो कांड हुआ एक हरिजन परिवारके साथ उसका जो विवरण दिया है, वह बहुत अधूरा है । आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ, यदि आप उसका पूरा विवरण सुनेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि इन्सान तो क्या, हैवान भी वैसा नहीं कर सकता है । यह केवल किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं, सारे देश के लिये शर्म की बात है । इस प्रकार के कांड जब हमारे देश में होते हैं तो हमारे देश का मस्तक नीचे झुक जाता है ।

हुआ क्या ? कहा गया कि इस गांव में 19 साल के एक हरिजन लड़के ने दो पीतल के बर्तन चुराये । उसको पकड़ लिया गया । उसने मान लिया कि मैंने दो बर्तन लिये हैं । उसको पीटा गया, चालीस आदमी उसको पीटने वाले थे । उसको पीट करके, जहां उसने वह बर्तन रखे थे, उस होटल के पास उसको ले गये । वहां उसको पंडाल के साथ, दोनों हाथ पीछे करके, रस्सियों से बांधा गया और डेढ़ घंटे तक चालीस आदमी उसे पीटते गये । सैकड़ों की तादाद में लोग वह सब देखते रहे । वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था । एक आदमी को क्या सूझी कि उसने दियासलाई ली और उसके कपड़ों में आग लगा दी जबकि उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुये थे । उसके थोड़े से कपड़े जल गये और वह चीखता रहा । उसके बाद वह आग अपने आप बुझ गई । फिर किसी दूसरे आदमी ने लालटेन में से तेल लिया और उसके कपड़ों पर छिड़क दिया और आग लगा दी । जब वह जल रहा था उसमें वह रस्सी भी जल गई जिससे कि वह बंधा हुआ था । इससे वह खाली हो गया जबकि रस्सी अपने आप जल गई और फिर वह बेहोश होकर गिर गया लेकिन किसी न उसे उठाया तक नहीं । थोड़ी देर में जब उसे होश आया तब वह रेंगता रेंगता बराबर में एक डाक्टर के पास पहुंचा । आपको आश्चर्य होगा कि उस डाक्टर ने भी उसकी नहीं सुनी और कहा कि तुम सरकारी अस्पताल में जाओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता हूं । वह रोता रहा और बेहोश पड़ा रहा । एक गरीब आदमी रिक्शे वाला उधर से निकला, उसने उसे साइकिल पर बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गया । वहां जाने के बाद एफ० आई० आर० लिखी गई और पुलिस स्टेशन वाले उसे बराबर के अस्पताल में ले गये । आपको आश्चर्य होगा कि 18 घंटे तक अस्पताल वालों ने उसके कोई दवाई नहीं लगाई, वह वैसे ही पड़ा रहा । उसके बाद पुलिस उसे उस अस्पताल से निकाल करके विजयवाड़ा के अस्पताल में ले गई जहां पर जाकर वह मर गया । इसके एक साल पहले उसके पिता का भी देहान्त हो गया था । इस प्रकार का यह कांड हुआ जिससे सारे देश की आंखें खुल जानी चाहियें । हां, उसकी जेब में कुछ पैसे भी थे । जब वह जल गया तो उसकी जेब से पैसे निकाल कर बराबर की दुकान से शराब खरीदकर वे लोग पी गये ।

अब आप देखें कि यू० पी० के अन्दर क्या हुआ । कोई हरिजन स्त्री थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था । वह कुयें पर पानी लेने के लिये जा रही थी । उसने अपने बच्चे को खाट पर बिठा दिया । जो आपने

[श्री कंवरलाल गुप्त]

आप को बड़ी जाति का हिन्दू कहलाने वाला था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उस बच्चे को उठाकर कुयें में डाल दिया इसलिये कि कोई हरिजन का बच्चा उसकी खाट पर कैसे बैठ गया। जब उस बच्चे की मां ने प्रोटेस्ट किया कि यह क्या कर दिया तो, उस औरत की गोद में भी जो तीन साल का बच्चा था, उस बच्चे को भी उसने छीनकर कुयें में डाल दिया। इस प्रकार की हालत हमारे देश की है। इसको देख कर और सुन कर शर्म आती है।

महात्मा गांधी के देश में जिन्होंने अपना सारा जीवन हरिजनों के उद्धार के लिये दिया, स्वामी दयानन्द के देश में जिन्होंने अपना सारा जीवन इस काम के लिये न्योछावर किया और इस देश में जिसकी सभ्यता सारे इन्सानों को एक जैसा मानती है, किसी भी महजब का हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है इस प्रकार के देश में जहां की ऐसी संस्कृति हो वहां पर आज बीसवीं सदी में इस प्रकार की घटनायें हों, यह सभी के लिए एक चैलेन्ज है। इसमें किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह सारे देश के लिए एक चैलेन्ज है। यह देश प्रगति कर रहा है लेकिन सही मानों में जो दृष्टिकोण होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो रहा है। यह एक ऐसी ट्रेजेडी हुई हैं जिससे शायद हमारा देश कुछ जाग जाये। और अगर हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करें तो हो सकता है कि कुछ हालत सुधरे।

कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के अन्दर ही एक इसी प्रकार की घटना हुई थी। वह शायद इधर के समाचार-पत्रों में नहीं आई। उसमें क्या हुआ? कुछ बड़े जमींदार लोग वहां के हरिजनों की जमीन हथियाना चाहते थे। उनको वहां पर बंजारा कहा जाता है। जब उन लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की तो उन बड़े लोगों ने करीब डेढ़ सौ गुन्डों को हायर कर के उनके ऊपर हमला कर दिया और 15–20 महिलाओं के साथ रेप किया गया और उनको लूटा गया। यह बात केवल अखबारों की ही नहीं है, आंध्र प्रदेश की असेम्बली में भी इस सवाल को उठाया गया। वहां के समाचार-पत्रों में भी यह चीज आई है। लेकिन सरकार ने क्या किया? होम मिनिस्टर ने यह बात बताई थी और उन्होंने ठीक ही कहा था कि वे इसमें व्यक्तिगत रुचि रखते हैं और अगर इसमें ढिलाई होगी तो वे उसका इन्तजाम करेंगे। मैं उनकी बधायी देता हूं लेकिन उनकी सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 1 सितम्बर 1967 को जो ट्रेजडी हुई उसमें क्या हुआ। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ा उनकी पिटाई की तो आंध्र प्रदेश की सरकार के एक मिनिस्टर इरीगेशन मिनिस्टर उनको शील्ड करने लगे। पुलिस ने जो उनकी पिटाई की तो वह जख्म चीफ मिनिस्टर को दिखाये गये और जिन पुलिस वालों ने उन गुन्डों को गिरफ्तार किया था उन पुलिस वालों को ही उन्होंने सस्पेन्ड करवा दिया।

यह जो बड़ा आदमी था यह वहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट का बड़ा भाई है। (शेम शेम) मैं इस को पार्टी का सवाल नहीं बनाना चाहता और इस तरह के कांड चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्त्ता द्वारा किये जायं वह एकदम अनुचित हैं और ऐसे आदमियों को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए।

इसी प्रकार से यह जो दूसरे कैंडिडेट के बारे में 28 मार्च को गृह मंत्री जी ने जिक्र किया मैंने सुना है कि उस कांड के लिए जिम्मेदार वहां की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। वह उस कांस्टीट्यूएंसी से आया है और वहां के जितने बड़े लोग हैं वे उस की मदद पर हैं और यही वजह है कि उस मामले में ढिलाई हो रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा इस में कोई पार्टी का सवाल

नहीं है । यह किसी राजनीति का भी सवाल नहीं है । मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे वह हमारी पार्टी का आदमी हो, चाहे आप की पार्टी का आदमी हो, कोई भी इस तरह की बेजा हरकत करे, गलत काम करे, उस के लिए किसी भी पार्टी में स्थान नहीं होना चाहिए । मंत्री महोदय इस बात को देखें और अगर इस प्रकार की कोई चीज हो तो उसे उन्हें दूर करना चाहिए और जो इस प्रकार के लोग हैं उन को उन्हें अपने दल से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए । इसी तरह से अगर कोई जनसंघी ऐसा काम करे तो मैं कहूंगा कि उस के लिए भी जनसंघ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और उस को भी निकाल देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी (*व्यवधान*)

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो यह शुबहा है कि वहां की पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है तो मैं आप के जरिए गृह मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि सभी राजनैतिक दलों के और सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की आप एक मीटिंग बुलाइये और वहां पर यह स्पष्ट करिये कि इस बारे में सारे देशवासी एकमत हैं और इस को लेकर किसी दल के बीच मतभेद नहीं है और यह कि इस तरह की बेजा हरकत करने वाले चाहे किसी भी दल से सम्बन्धित क्यों न हों उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए ।

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के 20 वर्ष बीत जाने पर भी ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटें यह बहुत ही अनुचित बात है और सरकार को सक्रिय कदम उठा कर और अपराधी लोगों को कड़ा दंड दिला कर इस तरह की गलत चीजों को बन्द करना चाहिए । हमारे संविधान के जो डाइरैक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 46 में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा । यह होने के बाद भी अगर यह इंसिडैंट्स हमारे देश में होते हैं तो इस के लिए उन्हें कोई मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें कि यह फैसला किया जाय कि इस तरह के कांड किस तरीके से रोके जायं । यह जो शर्मनाक कांड हुए हैं उन के लिए मेरा कहना है कि मंत्री महोदय एक सैंट्रल एजेंसी के जरिए उन की इनक्वायरी करायें और जो अपराधी हों, उनको दंडित किया जाय ताकि लोगों को इस बात का विश्वास हो सके कि सरकार कड़ाई के साथ ऐसे लोगों के साथ पेश आना चाहती है । यह जो लोगों को शुबहा है कि वहां पुलिस पर कोई पोलिटिकल दबाव है चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो अथवा आंध्र प्रदेश में हो, कहीं भी अगर इस तरह का नाजायज दबाव हो वह उनका शुबहा हट जाय और लोगों के दिलों में एक विश्वास की भावना पैदा हो जाय । मैं चाहता हूं कि दो, तीन जगहों पर जहां यह कांड हुए हैं वहां पर गृह मंत्री, प्रधान मंत्री महोदया और पार्लियामैंटरी कमेटी के कुछ लोग जायं और उन मामलों की इनक्वायरी करायें और इस तरह से तमाम लोगों को इस का विश्वास दिलायें कि यह सदन और यह देश इस चीज को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक देखता है और सही तरीके से उन कांडों की पुनरावृत्ति को रोकना चाहता है ।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चीज का रूट काज क्या है, इस को भी हमें देखना पड़ेगा । दरअसल यह सोशियो-एकोनामिक प्राब्लम है । आजादी प्राप्ति के 20 साल बीत जाने के बाद भी हमें इस बात का दुःख है कि जितना इस गरीब और दलित वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए था वह अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है । जरूरत इस बात की है कि हम उन को ऊपर उठायें । जब तक हम इस चीज को नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

[श्री कंवरलाल गुप्त]

अध्यक्ष महोदय, आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मैंने उस में पढ़ा कि राजस्थान के अन्दर एक पंचायत है और उस पंचायत के अन्दर एक हरिजन सदस्य है और जब उस पंचायत की मीटिंग होती है तो बाकी सदस्य तो कुर्सियों पर बैठते हैं लेकिन वह हरिजन सदस्य नीचे बैठता है । वह त्रिपाल पर भी नहीं बैठता है ।

आज भी हरिजनों के साथ मंदिरों और कुंओं के मामले में भेदभाव किया जाता है । इस तरह की चीजें अब कम से कम रुक जानी चाहिएं ।

घंटी बज चुकी है मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त किये दे रहा हूं । सर्विसेज में सन् 1960 में शेड्यूल्ड कास्ट्स का परसेंटेज 17.19 था । 5 साल के बाद 1965 में वह 17.19 की जगह 17.17 रह गया यानी बढ़ने के बजाय और कम हो गया । यह आंकड़े मैंने उस रिपोर्ट में से लिये हैं । जाहिर है कि जब तक उन लोगों का स्टेटस नहीं बढ़ेगा तब तक यह छुआछूत रहेगी । इसी तरीके से क्लास वन अफसरान का परसेंटेज सन् 1960 में 1.16 था जोकि सन् 1965 में 1.59 परसेंट हो गया । उन का स्टेटस बढ़ाने के लिए उनको एजुकेट करना चाहिए, उन में लिट्रेसी को बढ़ाना चाहिए । इस के लिए और अनुदान स्वीकृत करने चाहिएं ताकि उन का उद्धार हम कर सकें और उन को ऊपर उठा सकें । थर्ड फाइव इयर प्लान में जो हम ने इस मद में 102 करोड़ रुपया दिया है उस का इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाता तो उस दिशा में बहुत कुछ हो सकता था । मेरा कहना है कि इस में बहुत सारा वेस्टेज होता है जिसे कि हमें रोकना चाहिए । हरिजनों के अन्दर लिट्रेसी भी जैसा मैंने कहा और लोगों की अपेक्षा कहीं कम है और हमें उनके लिट्रेसी के परसेंटेज को भी बढ़ाना चाहिए । मैं और अधिक न कहते हुए गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में गम्भीरता के साथ ध्यान दें और जो इस का कारण है उसे मिटाने के लिए सक्रिय कदम उठायें । मैंने जो इस के लिए दो, तीन सुझाव दिये हैं उन पर वे विचार करके बगैर पार्टी की बात सोच कर आल इंडिया लैविल पर इस मसले को हल करें वरना हमारे देश का भविष्य अंधकारमय है । इस प्राबलम को हल करके ही यह देश आगे बढ़ सकता है और पनप सकता है । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह प्राबलम बनी रही तो देश गिरेगा वह कभी उठ नहीं सकता और उस का भविष्य अंधकारमय रहने वाला है ।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay) Central): Mr. Speaker, Sir, Shri Kanwar Lal Gupta, while Speaking, spoke like a an advocate of his party, without understanding the basic problems as to why there are atrocities committed on the scheduled castes, scheduled tribes and the down-trodden people. He laid stress on the happenings under the Congress Government. . . . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I did refer to it.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): He referred to it with shame and emotion.

SHRI R. D. BHANDARE: I have not misunderstood him.

MR. SPEAKER: You should not waste time. If parties are brought in, you may not get at the main problem.

SHRI R. D. BHANDARE: He has forgotten what happened in Madhya Pradesh, in Bilaspur. We have got to pay our attention in this hon. House to this very important problem. Since the Prime Minister is here, the hon. House must also give very serious thought to the problem of these people,

as to why the atrocities are being committed, and why they are on the increase. Sir, twenty years have passed since we accepted our Constitution and the principles adumbrated in it—the principles of Justice, Equality, Liberty and Fraternity. Why is it that there is no semblance of Fraternity or their principles noticable in our country.

I will just explain as to what happened in Madhya Pradesh,—on whom were the atrocities committed. It was the Satnamis who were subjected to these atrocities. Who are these Satnamis, is the question. Satnamis are the people who read Ramayana and worship Lord Rama and who have changed their outlook. They would like to get out of the social stagnation in the society in which they are living. I would like to read out a passage—not a very long one, but a short one, containing a few sentences—from the *weekend Review*, published on the 24th February of this year. I quote:

> "In the Mungeli pocket and in the districts of Bilaspur, Raipur, and to a lesser extent, in Durg, there is a large sect of Harijans who are known as 'Satnamis'. It seems that in the time of Akbar, with Moghul armies mounting their attacks on this region, apprehensions of mass conversions arose. At this time a Hindu saint came to this area from the north, and with his doctrine of equality and piety, acquired a large following. He named his sect the 'Satnamis' (believers in truth). Though they belonged to the lowest castes, the Satnamis adopted a way of living which would do credit to the Brahmins."

These are the people who have been trying to get themselves out of the social stagnation. My hon. friend Shri Madhu Limaye had made a mention of the New Converts to Buddhism. He equated the problem of the Harijans with that of the Buddhists. The reason is that even though an untouchable or a member of the Scheduled Caste community embraces Buddhism, for the purpose of regeneration and reconstruction of the new Indian society based on the principles of *Prajna, karuna* and *sheela*, with the prayer in his mouth '*Buddham sharanam gachchami, Dhamum sharanam gachchami Sangham Sharanam gachchami;* the people do not take into consideration the new change that is coming in among these people. Whether one is a worshipper of Lord Ram or worshipper of Lord Buddha, people in this country are not mindful of the change at all. The result is that atrocities are committed on these people and they continue to be committed in all parts of the country irrespective of the Government or the parties to which that Government belongs. Why does it happen? It happens because the structure of the Indian society is determined by what is known as social determinism. My hon. friends the Communists and some others from the other side are under the impression that once the economic position of these people is changed, all the ills will be removed from these communities and they will find themselves in a better position. But it is not so. Indian society is essentially and necessarily based on the principle of social determinism as a principle because it is built on that principle.

Because of this social determinism there is inherent inequality at the base of the Indian society. Come what may, this inequality in the Indian society continues. I need not mention here how the different authors have tried to describe and ascertain the factors which determine the Indian society as being based on the principle of inequality. Social and economic power are in fact embedded in the social institutions and the attitudes of the Indian people. The result is that in spite of the fact that we have implemented three Five Year Plans and tried to change the economic face of the Indian society, economic power still continues to be concentrated in the hands of those whose minds and attitudes are not changed at all.

We have accepted democracy. I was therefore, under the impression that after the acceptance of the principles of democracy and the democratic way

[Shri R. D. Bhandare]

of life as a new way of life, there would be a change in the Indian society but because of this economic factor as a power embedded in the institution based on inequality, the political factor as a new force is also helping those institutions which are based on the principle of inequality. I, therefore, wanted to give an illustration of what happened in Madhya Pradesh. The Satnamis refused to vote for a particular party. The result was that as soon as the party which was not voted by those people came to power, they started oppressing them and started in fact atrocities. Therefore, unless the social relationship and the attitude are changed, there can be no social change and improvement in the lot of these people. So, what is to be done in this regard?

I shall enumerate the points one by one. The first is that there should be a radical change in the attitudes. Every individual, every political leader and every right-thinking individual must try to change his own attitude and the attitude of the Indian people towards these people. Secondly, we must guarantee these people a minimum income for the preservation of their life so that they could have self-respect and self-reliance.

Thirdly, we have to inculcate in them a sense of social security and social justice. Fourthly, we must see that they have a change of mind so that they could have a sense of participation in the development of Indian life. Unless these things are done, they will not rise in the social scale and they will not be able to give up their inferiority complex.

Otherwise, what will happen is that it will be just like 'Alice in Wonderland', the same scene, the same analysis, the same recommendations, the same criticism, the same explanation, and the same inaction on the part of those in power and authority or those in whom is vested economic and social power, and the same perpetuation of injustice will always continue, as it has done so far, as the order of the day.

MR. SPEAKER: Even at this rate, we will not be able to finish. So, I would request hon. Members not to put me in the position of having to ring the bell.

SHRI RAJARAM (Salem): I am really happy to participate in this discussion. Usually we use to discuss problems which arise abroad in matters of this type. If anybody has been hanged in any foreign country, a Negro in Africa or anybody else, immediately all MPs join together and raise a hue and cry. Now only our Government come forward with this proposal to consider anything like that happening in our country and say that we must give due consideration to it.

In this connection, I must appreciate the attitude of Shri Chavan who has come forward with a statement about the happenings in Krishna district and other places in India. I belong to a party which has the slogan: *Onre kulam, onre daivam*, which means 'one humanity, one God'. That is our policy in Tamil Nad. You will have never heard such kind of things happening in my part of the country. I am very proud of that. How has it happened?

Here the Congress Party has been ruling for the past twenty years. Even before that, in Madras State, people like the Maharaja of Pithapuram who ruled in the name of the Justice Party gave jobs to the Adidravidas, Scheduled Caste people, upto Deputy Collector level even in those days when Shri C. Rajagopalachari was Chairman of the Salem Municipal Board—Salem is my place—he joined with another gentleman by name Shri A. V. Raman, an engineer of that place, and conducted *sama pandi bhonan*, interdining. This was what was done 45 years ago at Salem. You know what

happened. Orthodox Hindus, Brahmins, joined together and celebrated a yagam to convert these people. That is how these people started a social revolution in that part of the country.

Another great and grand old man of the south, Periar Ramaswami, started a movement called 'self-respect movement'. He advised all people to discard their caste tails. Here in this Parliament I see Mr. Gupta, I was told it is a caste name. I am seeing Desais. It is a caste name. I am seeing Agarwals. That too is a caste name. In my part of the country, people are ashamed to have a tail behind their names. If the so called high-caste Hindus in the country do not come forward, after wielding power for twenty years, to leave their titles as Sharmas, Guptas and Desais, what will be the fate of the country?.. (An Hon. Member: Mudaliars and Chettiars also). Who is going to guard the Scheduled Castes? After the DMK came to power in Madras State, they made a provision in the budget for inter-caste marriages. I am asking the Central Government: why don't you do some social reform instead of always thinking in terms of power and power alone? I do not know why the Congress is mad after power alone. They must also come forward to do these things. I am sorry to say that U.P. which is considered to be the biggest province in India has produced three eminent Prime Ministers but has not produced a single social reformer as in Tamilnad. Any part of our country can be proud of our social reformers.

MR. SPEAKER: We are digressing from Harijans to social reform.

SHRI RAJARAM: The Scheduled Castes must be lifted from the cheries to the middle of the towns or middle of the villages. They must be given free land. We must cultivate the practice of inter-caste marriages between the Scheduled Castes and other castes. People from Tamilnad who had gone to Malaysia and other places as labourers have left off their castes and live a casteless society. I have twice visited Malaysia; they live happily. I do not know why we cannot cultivate this practice and encourage social reform. We have rejected the caste system in our State. As far as my party people are concerned, nobody knows to what caste they belong. They have been elected. We contested —and won—25 seats. Gandhiji started the movement against untouchability and casteism. That task is unfulfilled and it is we who must devote ourselves to that unfinished task of building a casteless society which was the ideal of Gandhiji.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad): It is a basic question which has been described in such a gruesome fashion by our friend from the Jan Sangh. Nobody protested when the Harijan boy was being burnt; nobody came out for giving him medical treatment. It is because of the fact that in this country feudalism has not been totally abolished. It is the Brahmin mentality that rules in this country. The other day when a Member from the Congress Party, Shri Shashi Bhushan spoke in the House that there should not be any Rajput regiment or Gurkha regiment but that there should be some nationalist regiment, and that people of the backward classes, Harijans should be included a few persons stood up in the House and said that there would be revolt in the country. Let there be Gurkha and Rajput regiments. But let there be there regiments also where others are equally accepted. This is the mentality. How can you unify the Harijans in this country? How can you treat well the minorities in this country? We know that on our border there is Pakistan and there is China. We know also there is the international press which wants to pull down the image of this country. The image of this country cannot go up if we do not treat our Harijans well, if we do

[Shri R. K. Sinha]

not treat our Muslims well, if we do not treat our backward communities well. In this respect, I would suggest to the Government that the land reform should be completely carried out. That alone will lead to the economic progress of these backward communities, and even at the cost of the upper classes there should be some privileges which must belong to the Harijans. For thousands of years in this country the Harijans have suffered. They have been denied all the opportunities of life and for all these 15 to 20 years also the Harijans have had to go with sack cloth and ashes before the upper classes in this country. If we want to see the image of Gandhi living in this country, if we want the future of this country, if we want the soul of the Mahatma to rest in peace and the soul of Jawaharlal Nehru to rest in peace in this country, the Harijans of this country must be treated well. We must launch a re-education campaign for the youth of our country. They need education; they need economic opportunity; to achieve this, the Government must come forward boldly.

Our friend from Jansangh was shedding crocodile tears, they talked about the obscurantist movements. I want to ask them when they take out the Goraksha Andolans in those parts of the country where cow-slaughter is practised, why do they not go forward for abolishing the caste system. They say there has been no reformer in the Indian National Congress. They do not know that for weeks together the father of the Nation, Mahatma Gandhi, was prepared to lay down his life for the cause of the unity and for the cause of the Harijans in this country. They also must know that Harijans today are Ministers in this country; they have such opportunities in this country because of the Indian National Congress whose heritage has been built up over the years.

When the Opposition parties encourage feudal elements and go into alliance with reactionary feudal parties, should they not think of the Harijans and their position today? They should look into this. The Harijans today are denied the opportunity. Why deny this opportunity? By illtreating the Muslims of this country, you are strengthening the hands of Pakistan and the hands of China. I would appeal to those who think that they are the only true nationalists: let them come forward with the movement which abolishes untouchability and remove this tar from the face of this country. There shall be no future for this country unless we integrate our Harijans with the rest of the community on the basis of equality. We must treat them better than our Brahmins and our Kshatriyas. Let the latter stand in the queue behind and the Harijans should come forward. Then alone in this country we shall achieve real equality, peace and progress.

SHRI P. R. THAKUR (Nabad-WIP): Sir, I am really very happy to get a chance to speak in this House. Perhaps because I am an Independent Member, I seldom get a chance to speak. I am thankful to you for having given me a chance this time to speak. The debate that is going on about the Scheduled Castes is very important and I myself being a Scheduled Caste Member I want to speak.

MR. SPEAKER: He ought not to speak; he should leave it to the upper classes then!

SHRI P. R. THAKUR: It has become a fashion in our country to highlight and bemoan acts of racialism outside India. We have been always very vocal in condemning the Apartheid policy of the South African Government. We are doing the same thing now about South Rhodesia. A simple news of a handful of white students preventing entry to Negro students in a school somewhere in South America gets wide publicity

in our newspapers. It is high time that the light should be turned inwards to see how millions of untouchables in this very country continue to suffer inhuman and shameful humiliations, in spite of 20 years of Independence. Every aspect of our life is infested with casteism and communalism.

There have been recent reports of some Scheduled Castes being shot in a North Indian State for having dared to grow moustaches. We know how a Scheduled Caste college student of Aligarh was murdered because of his appointment as a senior monitor of his college. The tale of atrocities committed recently on Satnami Scheduled Castes in certain Madhya Pradesh villages are too well-known to be repeated here. A little over a month back in Andhra Pradesh which is your State, Sir, a Scheduled Caste boy was roasted alive on a charge of pretty theft. There have been reports that Scheduled Caste women were stripped naked to walk before public on roads both in Maharashtra and in Andhra Pradesh, which is again your State, Sir.

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): The Andhra Government have made thorough enquiries and it is not true. (*Interruption*).

MR. SPEAKER: The Home Minister here has already denied it.

SHRI P. R. THAKUR: And now only a week back two Scheduled Caste children aged 7 and 3 were reported to have been killed by an enranged Thakur in a village near Kanpur in U.P. These are not a few isolated incidents. Such atrocities are perpetrated everywhere in our country due to the virus of casteism and untouchability, although practice of the latter has been banned by law.

We have voiced a demand in this very Parliament for the hanging of the South Rhodesian White Prime Minister for his naked racialism, but in spite of all the organized inhuman atrocities committed on the Scheduled Castes in various parts of the country there has been no demand from any quarter so far for hanging of culprits involved in these heinous crimes. The Governments concerned are only busy in whitewashing the black acts. In the case of Hindu-Muslim riots there have been suggestions for imposing punitive collective tax, etc., but our Government leaders have never thought of such a measure for stopping the organised crimes against the Scheduled Castes.

The authorities have failed to learn any lesson and to provide adequate protection to this unfortunate strata of society. The law against untouchability is practically inoperative because of the obviously indifferent attitude of so-called upper caste Hindus, holding key positions. It is distressing that the constitutional safeguards are not being implemented as provided. The decentralisation of administration has aggravated the situation in this sphere.

How are we going to solve this problem? There is not a single national leader or organisation dedicated to fight against this national evil. For Hinduism, the cow and other such things seem to occupy a more significant position than this problem of human dignity. The country has recently witnessed a strong agitation against cow-slaughter. But no organised campaign by any section of people has been heard of against the practice of untouchability.

The appalling silence of intellectuals and those in power and the complacency of society on this real challenge to the country is alarming. The Government should not ignore my hon. friend, Mr. S. M. Joshi's warning in the Lok Sabha in the course of a debate in August last year, that if the Government failed to take quick steps to improve the conditions of Scheduled Castes,

[Shri P. R. Thakur]

what Negroes were doing in America, Scheduled Castes might be forced to do it in India.

Unless we are able to wipe out untouchability, in any form, prevailing in our country, the hue and cry against racial discrimination is ridiculous.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Mr. Speaker, Sir, we are discussing a national issue and ever since that day when you directed that we should have a discussion in the House on this point, a line of Rabindranath Tagore is wandering in my mind. The Prime Minister understands a little Bengali—"

"এ আমার পাপ, তোমার পাপ"

"This is my sin and yours".

And my feeling is that it is wrong in the course of this discussion to be accusing each other. It is wrong of a Congress Member to claim a monopoly of progressivism and to say that he has a lesser degree of obscurantism than the Jan Sangh. It is wrong for any of us to point out that one particular party in power in a particular place is responsible. It is wrong for us to pose this problem as something which we can get away from by claiming superiority.

I was very astonished to hear the DMK spokesman. I am always ready to pay homage to the wonderful thoughts which have emanated from Tamilnad, but this song of superiority is getting rather too stale in our ears, and I want the DMK, if it has got a social philosophy which it can propagate throughout the country, not to confine itself to its own borders, but to come forward and co-operate with the rest of the country and to have real social regeneration.

So many years after independence we have got this kind of incident happening. What did Mahatma Gandhi say about it? I was looking at some of his works. Mahatma Gandhi wrote, I am quoting only one, in *Navjivan* of the 12th February 1922 on India's Swaraj:

> "Just as crops will not ripen without sunshine, so also we shall not reap the harvest of Swaraj till the darkness of untouchability is vanished."

He adopted an untouchable girl. She used to live in his ashram. Every day in the Sabarmati Ashram the day will begin with the incantation of the verse:

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्,
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं ।

I do not want heaven; I do not want to be born again; I do not want to be powerful; what I want is elimination of the suffering of my people. Mahatma Gandhi had suggested that, symbolically speaking, in our free India we should have an untouchable woman as the President of this country. Now, it is an emotional statement but, as a symbolic gesture, what have we done to proceed in that direction?

Today in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, in every other Pradesh we find instances of this kind happening. But I will say, at the same time, in Madhya Pradesh there is a non-Congress Government. Surely, they must accept responsibility for this. In Uttar Pradesh and Andhra Pradesh there are certain governments; I need not describe them, and when there are some statements coming out, linking up the governmental authority which connives at it, then surely the Centre should wake up. After all, the press report about the burning of the Harijan boy says:

> "Politically speaking, most of the Kapus and Kammas seem to be inclined towards the Con-

gress while the village's 1,600 Harijans are said to be under the influence of the Communists."

I am not making a song about it but, at the same time, it has got to be taken into consideration. I have been told, on the authority of a Member of this House, that in this village Kanchikacherla in Kammam district on the 1st of September many Harijan families were attacked by 150 goondas in order to evict them from the land. The land problem is at the root of all this mischief, and so many atrocities were committed, even rape was committed, in such conditions which I cannot possibly recapitulate here, as narrated by the Member. I also learn that some of the police officers, those who were trying to do their duty, were suspended because the people in authority there were in favour of it and they are Congress people.

I am not again going to make a very specific allegation, because it is likely to redound back to me again, but these things have got to be looked into, whether it is the Congress Province of Andhra Pradesh, or non-Congress Province like Madhya Pradesh or the middling Province—I do not know how to call it—like Uttar Pradesh, we have to find out what the position is and adopt certain things. Therefore, I feel that the Centre has a very special responsibility. Even in the Constitution there is a provision in regard to it. It is a human responsibility, and in this House I have been hearing over and over again—I have been here since 1952—from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe members a kind of call that just like Pakistan "give us Achuthistan might be our demand".

I have hear it from Congress Members of this House who have said it. We have found in Hindu society such dastardly diseases that so many of us had to find refuge in Islam and so many are going over to Buddhism. They are very welcome wherever emancipation is available for anybody. It is all right. But we know, at the same time, that emancipation will not come just like that. We have had so many inspiring documents asking us to do one good thing after the other. From Yajnavalkya to Vivekananda we have had an unwholesome surfeit of inspiration. What is necessary is not inspiration any longer but action, action in order to remove these disgraces of our country.

That is why I feel that we should all go ahead and pool all our resources. This is a social problem, an economic problem and a moral problem, all put together and I cannot claim superiority only because I have a social philosophy which is an answer to all the evils of the world. I have to work that philosophy in the objective conditions of my country, a country which has an obscurantist past and which carries the load of 4,000 to 5,000 years of history. To be a legatee is always a very difficult proposition. We are operating in perhaps the most difficult country in the world.

On an issue like this we should combine with a purpose and with a desire to root out the evil and to punish severely whoever was responsible. If lynching takes place in any part of India today, we have to take whatever methods are humanly possible in order to root out this evil and we should take every other step. So many of them have already been outlined—social, economic and others—which are absolutely indispensible to a solution of this problem.

I say, therefore, that we should not look at this problem from a partisan point of view. We should not shy off from accusations against political parties who might be exploiting their power in order to practise this kind of inhumanity. With

[Shri H. N. Mukerjee]

that end in view the Central Government should approach this problem.

SHRIMATI VIJAYA LAKSHMI PANDIT (Phulpur): Mr. Speaker, Sir, I am reminded today of the occasion more than 20 years ago when India focussed the spotlight of the United Nations on South Africa when people of Indian origin were being discriminated against. Our stand arose out of the policy which we followed during our independence movement and which was—an important plank—of the freedom struggle namely, that there must be complete equality in India, between all the people and every force of discrimination whatsoever should cease to exist.

It is sad that in the land of the Buddha, in the land of Mahatma Gandhi, in the land where we so constantly talk about moral purposes —and indeed we believe in them and try to follow them quite often—we should today, 20 years after freedom, witness this barbarous incident. It has not moved me as much as some Members here because I am well aware similar incidents are happening and happening all over the country from time to time; we do not take notice of them and action against them and gradually we cease to think about them. They happen because in spite of the pledge given in our Constitution there has been insufficient implementation of that pledge, no punishment of those who defy it and thus imperil the lives and honour of the lowest sections of the community.

Poverty is the most degrading thing in the world. It is sad and most pitiable. It demoralises the human personality. It reduces the person who is suppressed by it to sub-human conditions. The conditions that I have seen in some parts of my own State, not today but all my life and even today, are appalling and incomplete contradiction of the Constitution which pledges equality and dignity for all.

Let us not be misled by a few instances where people have risen above such circumstances and I would like to say today that unless priority is given to cleansing our social system and unless these depressed and suppresed people are spared the terrific burdens of poverty and ignorance, we are going to have to face in India a situation which will be very difficult to control. The people who suffer most are ignorant people. They are people who will go on suffering up to a certain time and after that if they revolt then the situation becomes extremely unpleasant. The point however, is not the unpleasantness of the political situation. It is that much of the trouble today has been aggravated, and I say this with a sense of responsibility, by political leaders. It is all very well to stand in this House and condemn an outrage in high moral tones. Let some of those who have spoken today look within themselves and see how they treat the untouchables in this country, in their homes and in their communities. Until there is a cleansing of the social structure in India, until there is a complete acceptance by every man and woman, no matter to what caste or class they belong, that it is the inherent birth-right of all sections of the community to be equal. We are not going to move forward through commissions and committees and appeals to Government.

Sir, I was in Allahabad the other day. We are talking of discrimination. I have come back a much sadder and a much wiser woman. I have no brief for any section, each community must stand up for itself in the final analysis in this country because the Constitution is behind there and gives them the safeguards. But are these safeguards allowed to function? Today, in Allahabad, the Muslim community is cowed down

and in a most pitiful condition. It is a truly shocking thing. Gandhiji always used to tell us that the question of freedom was not only to raise ourselves but also to free the British from thin guilt in suppressing us. So long as there is a section in India which is suppressed in any way we are all morally guilty.

One last word. Until we think clearly and face our problems squarely, I am very much afraid that the growing fear in the minds of the minorities will lead to consequences for which nobody will be responsible. I would like to join with other hon. Members in drawing the attention of Government to the urgent necessity of taking early steps by which the lowest of people in this country shall feel equal to the highest, not only under the law but in fact so that their lives are secure and they can live as honourable citizens contributing to the welfare of this country. If we are not progressing as fast as we can, it is because we have not given everybody a sense of equality; a feeling of participation. Once society is cleansed and strengthened we need to have no fear for India's future.

SHRI D. AMAT (Sundargarh): Mr. Speaker, Sir, I am grateful that I have been given some time to speak on the atrocities committed on Harijans in the south and some parts of the north.

India is the greatest democracy in the world with a total population of 51 crores out of which 65 million constitute the Harijans and 38 million constitute the scheduled tribes. All these people put together, with 40 lakhs of other backward classes, form 22 per cent of the population of India. These people are the weaker sections of the society. It is the constitutional and the bounden duty of the Government to safeguard their interests, to protect them, from all sorts of social injustices and to protect them from all kind of exploitation. This is the duty of the Government. But what is actually happening?

The gruesome tragedy that took place on the 22nd February, 1968, in Andhra, in the village called Kanchekacherla is a sad happening of inhumanity, heinous, barbarous and butcherous type for which the whole nation should hang her head in shame, for the atrocities inflicted upon an orphan, an innocent 19 years old Harijan by Kame Andhana, even after 21 years of Independence.

18 hrs.

It is astounding to reveal that his hands were tied behind and then tied to a pole of the pandal. He was heartlessly and mercilessly beaten continuously for 90 minutes while he was yelling in a heartfelt manner and confessing his fault. Still even after that, kerosene oil was poured on his cloths and he was set fire alive. The manner in which the boy was treated, I would like to describe it that he was killed, murdered and slaughtered in broad daylight. He was led like a sacrificial goat, to the altar of the goddess of the ill wish and whim of the caste-Hindu people to appease their anger. In this country we have heard that our Constitution has been burnt. We have also heard that our national flag has been burnt. Now we are hearing in this House that Harijans are being burnt alive. Yesterday evening I had been to Connaught Place where I overheard somebody saying that during the time of the Britishers Lord William Bentink, the system of Sati Daha Pratha was abolished, but our present Congress Government is introducing Harijan Daha Pratha, which of course is most inhuman. This is the remark that we hear among the public. I have read in the Ramayana that, when Sita was insulted by Ravana, his golden city of Lanka was reduced to ashes. I have read in Mahabharata that because of the insult to Draupathi in the broad daylight, the Kauravas were eliminated. I have read in

[Shri D. Amat]

the Hindu Treatise that because of the insult to Matha Parvathi, the Holy Yajna of King Daksha Prajapathi was marred. Now we hear that Harijan ladies being rendered naked and led in a procession. What would happen if these atrocities are inflicted on our Harijan women? What would happen to the lot of the country? It is the people who have to decide it in the long run. I condemn these atrocities.

In the educational field also, we are very much neglected in this country. I have no objection—I quite agree with the parents, who can afford to send their children to schools and colleges, getting them educated according to their choice and taste. But what about the education of the Adivasis, whose sons and daughters are sent to the Ashram school where one of the courses is how to hatch egg, which even my illiterate wife knows? IAS and IPS examinations are open competitive examinations, in which all the students who were educated in Oxford, Cambridge and convent, and also the children of Adivasis who were educated in the Ashram school, are required to appear. What is the net result? Naturally, the children of the others secure more than 70 or 80 per cent of marks and the children of the Harijans and Adivasis secure only 5 or 10 per cent, of the marks and this gives the Government a chance to say that our sons are not fit for IAS and IPS because they did not score the required marks. This is the position. Will a Harijan not like to become an Ambassador? Will an Adivasi not like to become the Governor of a State? We are singing the gospel of socialism. What is socialism? It means equal opportunities to all. I ask the Government whether they are going to give equal opportunities to us in connection with imparting of education to our children, and the answer is a straight 'no'.

As regards appointment in government service, what is the position? In the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1964-65, on page 101, it has been clearly admitted that the all-India yardstick to fill up 12½ per cent for scheduled castes and 5 per cent for scheduled tribes has not been fulfilled. This is the type of education that the Government is going to impart to our children. Still we speak of socialism. So, I condemn this type of education being imparted to our people. We want that type of education which will place our children on par with the children of the other people of India. I also condemn these atrocities inflicted upon Adivasis and Harijans. I condemn this type of Government, and with these words, I resume my seat.

श्रीमती मिनीमता अगमदास गरु : (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय हरिजनों की समस्या आजादी के बाद असाध्य तथा संक्रामक हो गई है क्योंकि गांधी जी ने एक सिद्धान्त चलाया था कि हरिजनों का उद्धार किया जाय। उनका उद्धार करने के लिये जब हिन्दुस्तान में कदम उठाया गया तो जो उच्च जाति के सवर्ण कहाने वाले लोग थे उनके लिए एक किस्म का सिर दर्द पैदा हो गया। उन्होंने इन बातों से चिढ़ कर हमेशा हरिजनों को सताना शुरू कर दिया जिसके कारण आज हरिजनों की यह दुर्दशा हो रही है। यह एक ही जगह या एक ही प्रदेश की बात नहीं है आज हर प्रदेश में इस तरह से अत्याचार, हत्या, लूट-खसोट और महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। यह बड़े दुख की बात है कि आजादी के बाद भी आज हम सिर उठा नहीं सक रहे हैं। जिस तरह से आज हमको कुचला जा रहा है उसके अन्दर हमें एक ही दृष्टिकोण दिखाई देता है कि इसमें कुछ राजनीतिक हाथ है। राजनीतिक हाथ इसलिए है—इस में दो किस्म की बातें हैं। एक तो यह कि जो उच्च जाति के लोग हैं, वे समझते हैं

कि अगर हरिजन लोग ऊपर उठ जायेंगे, तो हमारी गुलामी कौन करेगी, हमारा काम कौन करेगा । यदि इन में थोड़ी भी जागृति आ जाय, यदि इनमें थोड़ी भी विद्या आ जायेगी तो ये हमारे साथ समानता करने के लिये आगे बढ़ने लगेंगे । इस वजह से, अध्यक्ष महोदय, वे हमेशा हरिजनों को कुचलने की कोशिश करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि हमेशा से हरिजन गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलते आ रहे हैं और यही कारण है कि हमेशा उन्होंने एक ही दल को सपोर्ट किया है और वह दल है—, कांग्रेस । कांग्रस को सपोर्ट करने के कारण जिस जिस क्षेत्र में कांग्रेस विजयी हुई है, उस क्षेत्र में हरिजनों को दुर्दशा हमेशा से होती आ रही है । जैसे हमारे पिता जी ने कहा— हमारे अध्यक्ष जो, उसी क्षेत्र के हैं, जिस क्षेत्र में यह अत्याचार हुआ है, किन्तु उसके पिछले हिस्से को भी आप देखिये, जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब भी उसी क्षेत्र से जीत कर आये थे, तो उनको सताने वाले दूसरे ही होंगे, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस तरह से हमारे साथ होता आ रहा है ।

गांधी जी के सिद्धान्तों पर चल कर हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करने के कारण उनके लिये भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है । इस चीज को अच्छी तरह से अध्ययन कर दूसरे दल के लोग योजना बना कर हरिजनों को सताने की कोशिश कर रहे हैं । उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश को लीजिये— मध्य प्रदेश का मुंगेली कांड इतना भयंकर काण्ड है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है । उस काण्ड पर यहां इस सदन में अनेक लोगों ने समवेदना प्रकट की, दूसरे दल वालों ने भी समवेदना प्रकट की लेकिन हमारे मध्य प्रदेश शासन ने खास कर हमारे गृह मंत्री जी हमेशा यह कहते आये हैं कि मुंगली काण्ड एक प्रचार का साधन है यह सरासर झूठ है । दो शब्द समवेदना प्रकट करने के बजाय हमेशा उस बात को उन्होंने झूठ साबित किया । इसलिये मध्य प्रदेश के शासन से हमको संरक्षण कैसे मिल सकता है, हम कैसे विश्वास करें कि वहांपर हमारा संरक्षण हो सकता है । इसलिये मैं चाहती हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा उन हरिजनों की रक्षा की जाय जहां कि वे हमेशा से सताये जा रहे हैं

यहां पर श्री बाबूराव पटेल ने 1 अप्रैल को एक प्रश्न रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिनीमाता ने अपने अनुयायियों के साथ मुसलमान हो जाने की धमकी सरकार को दी है । यह सरासर गलत है—मेरे वाक्य को चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा नहीं होने दिया । चीफ़ मिनिस्टर साहब से मैंने कहा था कि यदि हम मुसलमान होते, मेरे वाक्य को चीफ़ मिनिस्टर साहब पूरा सुने बिना तुरन्त बोले कि आप मुसलमान होना चाहती हैं. कल होने वाली हैं तो आज हो जाइये । इसका कारण है, वे ऐसा क्यों चाहते हैं—आप लोग ईसाई हो जाइये मुसलमान हो जाइये लेकिन हिन्दू मत रहिये क्योंकि हिन्दू रहेंगे तो हमारा पूरा अधिकार आप चाहेंगे । इस वजह से हरिजनों को इतना सताया जा रहा है ।

मेरे उस वाक्य को तोड़-मरोड़ कर युगधर्म ने छापा तथा जो जनसंघियों का अखबार "आर्गेनाइजर" है उस ने छापा और उसी बात को लेकर श्री बाबूराव पटेल ने वह प्रश्न यहां रखा । "नई दुनिया" ने भी मेरी उस बातचीत को अपने 3 फरवरी के अंक में छापा था जिसका थोड़ा सा अंश मैं आपको पढ़ कर बताती हूं—गोविन्द नारायण-सिंह जी से मेरी जो बातचीत हुई थी उस की कुछ बातों को तोड़-मरोड़ कर जनसंघ के स्थानीय मुखपत्र ने छापा था जिसके बाद आर्गेनाइजर ने उसका प्रचार किया तथा श्री बाबराव पटेल ने यहां पर प्रश्न रखा । धर्मयुग और आर्गेनाइजर की बातें गलत रिपोर्ट पर आधारित हैं । मुख्य मंत्री से अपनी

[श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु]

बातचीत के दौरान में मैंने कहा था कि हरिजनों को भेड़ बकरी की तरह काटा जा रहा है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है । यदि हम मुसलमान होते तो बड़े-बड़े नेता और बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में दौड़ कर आते— ऐसा मैंने कहा था । जिस समय मुख्य मंत्री जी से यह बात-चीत हुई कुछ पत्रकार भी वहां उपस्थित थे । "नई दुनिया" की कटिंग मेरे पास है, यदि आप कहेंगे तो मैं दे दूंगी । एक संसद सदस्य ने इस तरह की झठी जानकारी के आधार पर मेरे ऊपर और मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाये हैं । यह एक ही प्रदेश की बात नहीं है, हर जगह हरिजनों के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं । ऐसी अवस्था में वे किस प्रकार जिन्दा रह सकते हैं ।

मेरे दो तीन सुझाव हैं । कई लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज्य में भी होता आ रहा था और अभी भी होता है । तो कहीं कहीं कांग्रसियों ने त्याग भी किया है और कहीं कहीं पर नहीं भी किया है । तो मेरा सुझाव यह है कि हरिजन आदिवासियों की सुरक्षा के लिये तत्काल व्यवस्था की जाय । यदि आवश्यक हो तो हमारे लिये अलग से कानून बनाया जाये ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि उन पुलिस अफसरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये जो कि इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में असमर्थ होते हों । जिस जिले के हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार हो उस जिले के कलक्टर, एस० पी० और डी० एस० पी० को तुरन्त स्थानान्तरित किया जाए ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जिस प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसी घटनायें हो रही हों उस प्रदेश की सरकार को साम्प्रदायिकता का हिस्सेदार माना जाये और वहां पर केन्द्र का हस्तक्षेप किया जाय ।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म करते हैं उसे सरकार की ओर से चेतावनी दी जाए और अगर उसके कार्यकर्ता अपनी हरकतें बन्द न करें तो उस विशेष क्षेत्र में उस पार्टी की शाखा को गैर-कानूनी घोषित किया जाय चाहे वह कोई भी पार्टी क्यों न हो ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं इसलिये मैं यहीं पर समाप्त करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोलहू प्रसाद, दो मिनट ।

श्री **मोलहू प्रसाद** (बांसगांव) : दो घंटे में सिर्फ दो मिनट? क्या यहां भी भेदभाव का मामला चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बोलो बोलो ।

श्री **मोलहू प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय 28 तारीख को यहां संसद में जो मामला उठाया गया था उसके सम्बन्ध में मैं आपको एक अखबार की खबर बतलाऊं कि आखिर सत्यता पर किस तरह से परदा डाला जाता है । चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहें मध्य प्रदेश हो और चाहें दक्षिण प्रदेश हो कोई भी प्रदेश हो, जिन लोगों की समस्या पर हम बहस कर रहे हैं उनके पास न तो कोई कवि है, न भांट है और न कोई कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार और न कोई अखबार है, कोई भी उनका नहीं है यह सरकार भी उनकी नहीं है । संसद में यह मामला उठाया गया था । यह अखबार है "स्वतन्त्र भारत"—पता नहीं स्वतन्त्र भारत है या परतन्त्र भारत है । इसमें खबर छपी है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कल बंगलौर के एक समाचार-पत्र में छपे इस समाचार का खंडन किया है कि महबूबनगर जिले के एक गांव में हरिजन औरतों को नंगे

होकर गांव में घूमने के लिये विवश किया गया । दो दिन पूर्व लोकसभा में गरमा-गरम बहस हुई थी और कल एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच की और जांच से पता चला कि महबूबनगर के जिले के किसी भी गांव में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, उस हरिजन ने दो बर्तन चुराये तो उसको फूंक डाला गया तो इस सत्यता पर जो परदा डाला गया है उस अखबार के एडीटर को भी फूंक देने के लिए क्या गृह मंत्रालय आदेश देगा ?

दूसरी बात यह है कि इन के पास इस देश में सदियों से आज तक इनके हाथ में न तो कलम रही है और न डंडा रहा है । वही कलम लिखने वाली जिसके हस्ताक्षर से इस देश में कैसे खर्चा चलता है और कैसे फैसला होता है । तो इनके हाथ में आज तक न तो कभी कलम आई और न डंडा आया : बीस वर्ष का जनतन्त्र हो गया, चाहे कांग्रेसी सरकार हो या गैर-कांग्रेसी सरकार हो, किसी भी प्रदेश का गृह मन्त्रालय आज तक कभी भी अनुसूचित जाति के हाथ में नहीं रहा । अनुसूचित जाति के लोगों को आज जो फूंका जाता है, जलाया जाता है, तंग किया जाता है या मारा पीटा जाता है, आप गृह-मंत्रालय को अनुसूचित जाति के हाथ में दे दीजिये और फिर देखिये कि किस प्रकार हरिजनों को फूंका जाता है या जलाया जाता है । लेकिन यह तो आपकी नीयत में ही नहीं है ।

जहां तक कलम का मामला है, देश का कोई भी महत्वपूर्ण पद ऐसा नहीं है जिस पर कि एक भी अनुसूचित जाति का आदमी हो । केवल एक ही उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है जिसमें कि एक अनुसूचित जाति का आदमी इस वक्त लिया गया है । लेकिन लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वह भी कोई ऊंची जाति का है, उसने तुरन्त इस्तीफा दे दिया क्योंकि अछूत लोकसेवा आयोग में आकर घुस गया था । इस देशमें कभी न तो कोई राज्यपाल और न कोई विदेश का राजदूत अनुसूचित जाति का बनाया गया । जिस पार्लियामेंट में हम बहस कर रहे हैं शायद यहां भी सरकारी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है । प्रधान मंत्री बैठी हैं अगर कोटा पूरा हो तो वह जरा विवरण बतायेंगी । आज भी यहां कोटा पूरा नहीं है । फिर यह तो लोअर हाउस है, जो अपर हाउस है उसके लिये संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है और न ही विधान परिषदों के लिए कोई उपबन्ध है कि उनमें अनुसूचित जाति का कोई रहेगा जब हिन्दुस्तान के मामलों को सुलझाने के लिये 22 बार संविधान में संशोधन किया गया तो क्या अनुसूचित जाति की समस्या को हल करने के लिए एक बार भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है ? अगर आपकी नीयत होती तो संविधान में संशोधन किया जाता लेकिन आपकी नीयत तो है ही नहीं ।

एक माननीय सदस्य ने जब उस दिन प्रश्न उठाया तो कहा गया कि इस मामले की जो जांच होगी तो उसमें अनुसूचित जाति का कर्मचारी रहेगा । लेकिन यहां आने के बाद साल भर से मैंने देखा कि यहां पर एक से एक बढ़ कर पटनायक और छलनायक हैं, वे चाहे जितना भ्रष्टाचार करें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती, लेकिन दिल्ली की पुलिस जिसमें 75 फी सदी अनुसूचित जाति के लोग थे, उन्हें तुरन्त डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हड़ताल कर दी थी । लेकिन गृह मंत्रालय पर कार्यवाही करने के लिये कोई भी उतारू नहीं है ।

जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, खुद मेरे क्षेत्र में ही एक अनुसूचित जाति के आदमी का कत्ल कर दिया गया । मजूरी ग्राम, थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, के एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी का कत्ल कर दिया गया । उसका नाम बाबूलाल था, लेकिन उसके ऊपर परदा डाला गया, कोई भी

(श्री मोलहू प्रसाद)

कार्यवाही नहीं हो रही है । इसलिए क्योंकि यहां लोक सभा में और विधान सभाओं में तो अनुसूचित जाति के आदमी मिल जाते हैं उनका कोटा पूरा हो जाता है लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोटा पूरा करने के लिये आपको आदमी ही नहीं मिलते हैं । जब यहां पर प्रश्न किया जाता है तो यह उत्तर दे दिया जाता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से कि आदमी कुशल नहीं हैं, लायक नहीं हैं । यहां सरकार बनाने के लिये तो उनका कोटा पूरा हो जाता है, वे लायक बन जाते हैं । लेकिन वहां के लिये लायक नहीं रहते । मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं । केन्द्रीय श्रम संस्था, गोरखपुर में अनुसूचित जाति के तीन कर्मचारी भर्ती किये गये ..... (व्यवधान) ..... 94 कर्मचारी इसमें थे जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क थे । लेकिन जब छंटनी की गई तो अनुसूचित जाति के उन तीन कर्मचारियों को ही निकाल दिया गया और उस अनुपात में सवर्ण जाति के कर्मचारियों को नहीं निकाला गया । इस सम्बन्ध में तीन बार प्रश्न पूछा गया लेकिन श्रम मंत्रालय जो है, वह तो बेशर्म मंत्रालय है, आज तक उसने जवाब ही नहीं दिया कि आखिर अनुसूचित जाति के उन कर्मचारियों को क्यों निकाला गया और उसी अनुपात में सवर्ण कर्मचारियों को क्यों नहीं निकाला गया । इस तरह की जो आपकी नीयत है जब तक वह दुरुस्त नहीं होगी तब तक देश में इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है । जब तक उनके हाथ में डंडा नहीं आयेगा और जब तक उनके हाथ में कलम नहीं आयेगी तब तक उनको इस तरह से फूंका जाता रहेगा और उनके कत्ल होते रहेंगे ।

MR. SPEAKER: The hon. Prime Minister.

श्री मोलहू प्रसाद : एक दो मिनट और ।

MR. SPEAKER: Will you please sit down now? You have taken—not 3 minutes—but ten minutes. I have called the Prime Minister.

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कैसे कुकर्म होते हैं वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी मैं आप को देना चाहता हूं

MR. SPEAKER: Order, order. It is not proper. Will he kindly sit down? I am on my legs. People who do this try to get more opportunity like this. It will be unfair to people who sit down like Shri Hiren Mukerjee and other Members who sit down correctly in time. This is not proper. The Congress party has got 100 names. I cannot call all of them. I have called Shrimati Minimata and others.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): let those Members of the Congress party who are waiting be also kindly allowed to speak. (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Please sit down. There is a Chief Whip for his party. He need not take it up. Every party must have some discipline' Every party has given some names. I cannot answer every hon. Members. Every party gives me a list and then I call the Members. The Prime Minister.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, I rise with a very heavy heart to express my sense of shock, sorrow and, if I may say so, shame on these barbarous atrocities which have taken place, and even more, that we should be so lacking in social consciousness after all these years that such incidents are happening all over the country.

It is, as one hon. Member has said, a national shame and I think we should not utilise this occasion to speak about one aspect or another. We do all of us share this shame and the only way in which we can wipe it out is at least

now, instead of blaming ont another, to try and see how we can work together to change attitudes, and to try and create a better atmosphere for our brothers and sisters who are Harijans, who are tribals and who are in the minorities.

Prof. Mukerjee said that we are burdened with the weight of thousands of years, but the weight is increased perhaps a hundredfold, on those who are not merely small minorities but vast number under-privileged, who have had not only the burden of history but the burden of being oppressed by their own brothers for these thousands of years. It is up to us to see how we can lighten the burden. It is not an easy task because of the numbers involved and even more so, because of the habits of thought and of living. It needs a revolution, a revolution in thinking, and it needs tremendous courage, intellectual courage, moral courage and even physical courage in order to tackle this tremendous problem. And it is a problem which we cannot tackle merely by giving jobs. That is important; I will not deny the importance of it. It is important to give equality of opportunity, but it is in our daily handling of these situations, in the way in which we behave towards these people, that the change has to come, and it is only when that change comes that the other things will also be possible.

We have to get together to fight all such feelings of class of caste and of communalism. We must also get together to refrain from making provoative statements or speeches. We mus get together to calm emotions when they arise. Mrs. Pandit mentioned about the fear in some communities in Allahabad. I have myself seen such fear in the eyes of the citizens, and as the rightly pointed out, fear is the most dangerous of emotions. When one is afraid, one is not in control of oneself. Therefore, we must see that conditions are not created in which any community has ea or a feeling of insecurity. These are the two greatest dangers.

We have talked a great deal today in the debate on the Ministry of External Affairs on Pakistan and China. I believe that we are fully able to meet those dangers, but if this danger within our country is not met, then we can fall prey to outside enemies. Today it is urgent that we work together to create equal opportunities for all our citizens, specially those who are underprivileged and that we work to strengthen the fundamental unity of our people. I cannot find words which are adequate to condemn these barbarous and heinous crimes. I cannot comprehend the cellousness, the insensitivity and the inhumanity of those who just watched a young boy being burnt to death. But, as I said earlier, it is not enough to blame these people. We have to blame the whole social system. It is not enough to blame the social system, unless we are prepared to take action to change that system and to create some hope of the basic human values to our people. Certainly those who are guilty must be punished and punished harshly. These are cases in which there should be no question of any kind of pity. But I would appeal to the House and to the country as a whole—let us get together and evolve ways of functioning in which we can take the necessary steus—economic, political and social steps—to create the necessary foundation on which a new life can be built and the equality and other basic rights, wich are the dues of all our people, can be given to them.

SEVERAL HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER: I will call two from this side and two from that side. About the other parties I know whom to call, but the Congress Party has given 20 names. I do not know whom to call.

SHRI THIRUMALA RAO: Andhra has figured very prominently. I would leave it to you to call one member from Andhra.

SHRI VISWANATHA MENON (Ernakulam): Sir, I am standing here to condemn the tragic incidents that

[Shri Viswanatha Menon]

have happened, particularly about the Harijan boy in Andhra. I see the incident not merely as a social problem. The problem is economic. You cannot shut your eyes to the facts of the case. What is the economic condition and social status of the Harijans? Have they got their own land? Are you prepared to solve the economic problem by giving them lands and also to raise their social status? Without doing all these things for the last 20 years, just coming here and indulging in tall talk and philosophic things is not going to solve the problem. This is not the only instance happening in Andhra. I have got a telegram today from Andhra which reads thus:

> "Eight Sugalis including two women brutally tortured. Landlord Kammavaripalem village, Krishna, Andhra suspecting Sugalis as thieves. One in dangerous condition. This village near Kanchikacherla where Harijan boy was burnt recently. Pradesh Congress and local Congress bosses exerting pressure to suppress case against culprits."

This telegram has been sent by the Taluk Ryots Sangam. Here everybody is of the view that we should condemn these things. What is the meaning of mere condemnation when such things are happening? Who is responsible for it? Everybody has to admit that the main responsibility for this lies with the government, the party in power. You cannot minimise their responsibility.

We must look at the issue self-critically. Without doing that, saying something philosophically will not solve the problem. You are declaring that you are going to have socialism in this country. Then, are you prepared to give land to the tiller, land to the poor? Most of the harijans are poor. There may be exceptions like Shri Jagjivan Ram, but most of them not poor. They are workers. Are you going to help them economically? By giving some harijans the posts of Ministers or Governor you are not going to solve the problem. Are you prepared to help them economically? That is the basic question.

Shri Bhandare was saying something about Buddhism and other big things. That would not solve the problem, because their problem mainly is economic. If there is a rich harijan girl, a poor caste Hindu boy is ready to marry her, then the question of caste will not arise. So, it is only a question of money. So, are you prepared to solve the problem that way? You have preached socialism for the last 20 years. Have you done anything concrete in that direction?

I agree with the sentiments expressed by Shri Hiren Mukerjee, but I do not agree with his conclusion, because he says everybody is responsible. Saying that is not going to solve the problem. The question is: are you prepared to give land to the poor, to the harijans? Instead of that, you are now evicting the harijans from the land. What action have you taken to prevent such evictions? In this particular case, a harijan boy has been caught for alleged theft and he has been burnt. I can understand if such a thing happens in America where the Negroes are being burnt by Ku Klux Klan. But here it seems to be worse. I do not know how it has happened. but I am sure that the Congress is equally responsible for it.

SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI (Khargme): What about the RSS?

SHRI VISWANATHAN MENON: Why do you bring in RSS? I would request the Prime Minister and the Home Minister to take note of it and check such incidents. I have got that telegram with me, with the name of the individual mentioned there. It is by Lakshi Narayan, Secretary, Ryots' Sangam.

How are they going to solve this problem? Mere high brow talk will not help. Mahatma Gandhi said that untouchability must go and he has worked for it. But what are you doing? Gandhiji taught all those things when he was not in power? Now you are in power and you are the so-called followers of Mahatma Gandhi. What have you done?

Without doing anything you are finding fault with others, saying the other party has not done anything. I want to stress here that you have to solve the problem economically. Giving some Governorship to an odd individual, even to Shri Sheo Narain, is not going to solve the problem.

MR. SPEAKER: I am not able to give him even time to speak.

SHRI VISWANATHA MENON: You have to give land to the tiller, land to the harijans and minimum wage to the workers.

SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI: Have you done it in Kerala?

SHRI VISWANATHA MENON: We have done it. That is why all the harijans are voting for us. They are supporting the United Front Government. You have to give them minimum wages so that they will at least get food twice a day. I would also request you to take action against the culprits, while trying to solve the problem at the economic level.

श्री साधूराम (फिल्लोर) : अध्यक्ष महोदय आज हरिजनों का जो मामला इस हाउस के सामने पेश है उन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में चाहे वहां कांग्रेस गवर्नमेंट हो या जन संघ गवर्नमेंट हो चाहे किसी और दल की हो चाहे हरिजनों ही की क्यों न हो उन लोगों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है वह एक अफसोस की बात है। वहां के लोग शुरू से लेकर आज तक हरिजनों को अपने से नीचा समझते हैं, वह चाहते हैं कि देश में उन लोगों को दबाया जाय। हिन्दुस्तान में हरिजनों की आबादी 15 या 20 करोड़ के लगभग है यह शुड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट से साबित होता है लेकिन फिर भी इस देश की आबादी का चौथाई हिस्सा हर तरह से मर रहा है और उस के साथ बड़ी बेइन्साफी हो रही है और इस की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और सैंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं यहां किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता कि फलां पार्टी वाले या फलां पार्टी वाले काम करते हैं लेकिन जो भी सारे देश में सवर्ण भाई हैं उन के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है चाहे वे किसी भी पार्टी से आते हों या ताल्लुक रखते हों।

मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उस के बारे में श्रीमती मिनिमाता ने बतालाया कि वहां पर जन संघ के भाइयों ने क्या किया है दूसरे प्रदेश में जाइयेतो वहां कोई और हो सकता है लेकिन जो भी कुछ हुआ वह ऐसी बात है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इन बातों में न जाता हुआ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और प्रेजीडेंट साहब की तरफ से कई जिम्मेदारियां अदा करने की बात हमारे कांस्टिट्यूशन में हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में हरिजनों के लिये बहुत से सेफगार्डस दिये गये हैं। अगर कोई स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट उन को वायोलेट करती है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि जुल्म करने वालों के खिलाफ कदम उठाये? क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उन पर यह जिम्मेदारी नहीं आती है कि वह उन जुल्मों को रोकें? अगर वह इस बात की परवाह नहीं करते तो स्टेट गवर्नमेंट और उस के अफसरों को क्यों नहीं हटाया जाता नौकरी से, क्यों उन को जुल्म करने दिया जाता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस के बारे में कदम नहीं उठाती है तो यह मसला

[श्री साधू राम]

हल होने वाला नहीं है और स्टेट्स इस को ीपायेगी।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों, में यह जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बीस साल बाद हमारे देश के लिये यह बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के जुल्म यहां पर होते रहें। गऊ की हत्या को रोकने के लिये यहां पर आन्दोलन होते हैं लेकिन आदमियों पर जो जुल्म होते हैं हैवानों की तरह उन को मारा जाता है उन को कत्ल व गारत किया जाता है, औरतों की बेइज्जती की जाती है, उन के साथ पुलिस की रूबरू और सरे बाजार रेप्स किये जाते हैं, लेकिन इस के लिये आवाज नहीं उठाई जाती है। क्या यह हमारे सारे देश के लिये शर्म की बात नहीं है? मैं चाहता हूं कि इस बात के लिये हर एक पार्टी को मुत्तफिक होना चाहिये और ऐसे जुल्मों के खिलाफ उन को आवाज उठानी चाहिये। अगर हमारे कांस्टिट्यूशन में इस सिलसिले में किसी किस्म की कमी है और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस से रोका नहीं जा सकता तो कांस्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाना चाहिये।

इस के साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस किस्म की किताबें हैं, चाहे वह हिन्दू धर्म की हों या किसी भी दूसरे धर्म की हो जो मजहब का मसला पैदा करती हैं जो हजारों सालों से करोड़ों आदमियों को गुलाम बनाने का प्रचार करती हैं, उन को बैन क्यों न कर दिया जाये? मैं कहना चाहता हूं कि 18 या 20 करोड़ आदमी इस तरह के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर जुल्मों को बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। आजादी के बीस सालों बाद भी इस देश में इस तरह की बातें होती हैं। ऐसी हालत में जिन लोगों पर इस तरह के जुल्म होते हैं वह अपने खून के उबाल को दबाये बैठे हैं। इस हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में भी 107 शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के मेम्बर हैं। इस मुल्क की आबादी का चौथाई हिस्सा आज अपने को रोके हुए बैठा है। आज उन की बिरादरियों पर जो तशद्दद होता है वह शर्मनाक बात है। अब वक्त आ गया है कि इस लोक सभा में उन की बात को सुना जाय। मैं यहां किस किस बात की चर्चा करूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस बात के लिये हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिये और देश को एक करना चाहिये। इस परिस्थिति को रोकने के लिये अगर हमें कांस्टिट्यूशन को भी अमेंड करना पड़े तो कर देना चाहिये। अगर देश में जाति पांत का झगड़ा चला तो पाकिस्तान और चीन के हमले का खतरा तो कम होगा, लेकिन इस आग के फूटने के बाद उस को सम्भालना मुश्किल हो जायेगा।

आज जिन लोगों के पास न मकान हैं, न घर हैं न दुकान न जमीन न सामान है वह भारतमाता जिन्दाबाद का नारा कैसे लगायेंगे? अगर इतने करोड़ों आदमियों ने रिवोल्ट कर दिया अगर उन के दिमाग में यह बात आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई हैं और उन को इस जुल्म और तशद्दद का हर तरह से मुकाबला करना है तो मेरा ख्याल है कि यह देश के लिये बड़ा हानिकारक होगा। उतना खतरा आपको दूसरे देशों से पैदा नहीं हो सकता है जितना कि इस देश में ही पैदा हो सकता है। मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस मामले को वे अपने हाथ में लें और स्टेट गवर्नमेंट्स को दबायें, उन पर जोर डालें या जरूरी हो तो उनको तोड़ दें और वहां पर राष्ट्रपति राज लागू कर दें। लेकिन इस तरह की घटनाओं को कभी भी वह बरदाश्त न करें। सख्त से सख्त

उनको उठाने चाहियें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं आपको वार्न करता हूं कि देश में आग लगने वाली है। आज रेजोल्यूशंज का वक्त नहीं रह गया है, रेवोल्यूशन का समय आने वाला है। अब देश में इस प्रकार की बेइंसाफी को किसी भी हालत में बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।

श्री राम चरण (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, हम लोग हजारों सालों से जुल्म बरदाश्त करते आ रहे हैं और अब हम आगे इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों पर जो जुल्म हुए हैं इसके कई कारण हैं। सब से बड़ा कारण इकोनोमिक और सोशल हैं। जिस आदमी की इकोनोमिक हालत अच्छी होती है उसका समाज भी थोड़ा सा साथ देता है लेकिन जिस आदमी के तन पर कपड़ा न हो और उसके पास रहने के लिए मकान न हो, वह भूखो नंगा फिरता हो, जिस के पास दो बीघा जमीन भी न हो उसकी न तो गांव में इज्जत है और न ही शहरों में। जिस के पास गांव में एक इंच भूमि भी नहीं है उसको गांव में बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता है और उनको कहा जाता हैं कि यह तुम्हारा हक नहीं है कि तुम वहां की जमीन पर टाट्टी तक फिर सको। इस वास्ते जब तक इन पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारी नहीं जाती है तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता है।

आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी सामाजिक स्थिति को भी सुधारा जाना चाहिये। इस क्षेत्र में मैं चाहूंगा कि सामाजिक सस्थाओं को आगे आ कर इनके कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिये। आर्य समाज ने आजादी से पहले इस सिलसिले में ठोस कार्य किया था। लेकिन आजादी के बाद यह सस्था भी चुप हो कर बैठ गई है। गो हत्या बन्दी के लिए तो उसने आल इंडिया मूवमेंट चलाई थी लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्यो नहीं अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए और यह जो सोशल ईविल है इसको जड़मूल से नष्ट करने के लिए वह कोई मास एजीटेशन शरू करती है, एजीटेशन शुरू करती है। क्यों वह सो गई है? मैं हिन्दू जाति से कहना चाहता हूं कि अगर मुल्क को जिन्दा रखना चाहते हो अगर इस कौम को साथ लेना चाहते हो तो पिछड़ी हुई जाति के लोगों को आप गले से लगाओ और इसको साथ ले कर चलो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुम्किन है कुछ अर्से के बाद यह जाति सैपरेट लैंड की डिमांड करे। अगर उसने ऐसा किया तो उसको मजबूर हो कर इसको करना पड़ेगा। कारण यह है कि हम ज्यादा देर तक जुल्म बरदाश्त करते नहीं जा सकते हैं।

अब आप देखें कि किस तरह से इसकी इकोनोमिक हालत सुधर सकती है। आप ने सर्विसिस में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया है। लेकिन आजभी लाखों की तादाद में इन जतियों के लोग बेकार फिर रहे हैं, सड़कों की खाक छानते फिर रहे हैं। लेकिन उनको सर्विस नहीं मिलती है। इन बेरोजगारों लोगों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम भी दर्ज करवा रखें हैं लेकिन कोई पूछता तक नहीं है। बी ए, एम० ए०, डबल एम ए०, एल० एल० बी०, आदि परीक्षायें पास कर लेने के बावजूद भी इनको नौकरियों में नहीं लिया जाता है। बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। यहां तक कि टैक्नीकल क्वालिफिकेशंज तक वाले बेकार फिर रहे हैं। कांग्रस की बीस साल से हकूमत रही है। लेकिन आप देखें कि क्लास 1 में एक परसेंट हो इनको रिप्रिजेंटेशन मिल सका है, और क्लास 2 में दो परसेंट मिल सका है और जहां तक क्लास 3 का सम्बन्ध है केवल आठ परसेंट ही इनको रिप्रिजेंटेशन मिला है। अगर यही हाल चलता रहा तो सौ साल में भी जो इनका कोटा है, वह नहीं मिल पायगा। इनके साथ

[श्री रामचरण]

न्याय हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि क्लास 1 और क्लास 2 की पचास परसेंट पोस्ट्स अब आप इनके लिए रिजर्व करें। अगर आपने ऐसा किया और बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की नौकरियों में लगा दिया तो फिर देखेंगे कि कैसे इनके साथ कोई अनुचित बात होती है कैसे इनके साथ बेइंसाफी होती है, कैसे इन पर जुल्म ढ़ाये जाते हैं। जब हमारा जज हो आई० जो० हो हमारे दूसरे अफसर होंगे पुलिस में हमारे लोग होंगे तो फिर किसी के साथ जुल्म हो, इसकी सम्भावना नहीं है। चव्हाण साहब होम मिनिस्टर हैं उन पर ये जुल्म नहीं होते हैं हम पर होते हैं, इसको हम कैसे और कब तक बरदाश्त करते रह सकते हैं। मैं चाहूंगा कि चव्हाण साहब गृह मंत्रालय में सैल बनायें और यह उसी तरह का होना चाहिये जैसा सी० बी० आई का है और हर स्टेट में इसको स्थापित किया जाए, इसकी शाखायें हों और यह सैल इन सभी शिकायतों की छानबीन करे और इस सैल में सभी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हों, ऊपर से नीचे तक आई० जी० से ले कर बाकी जितना स्टाफ है उस तक, तब आप देखेंगे कि हम पर जुल्म होने बन्द हो जाएगे।

अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब आर्डर कर देते हैं। लेकिन नीचे वाला जो सिपाही है जिस को पचास रुपये तनख्वाह मिलती है वह कोई परवाह नहीं करता है, वह भी हमारे गले पर छुरी चलाता है। जब किसी को कत्ल कर दिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट जब हम थाने में लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सारे देश में जो इस तरह की घटनायें हुई हैं उनका सर्वे किया जाए तो आपको पता चलेगा कि हरिजनों की इन बीस सालों में कम से कम दस हजार हत्याएं की गई हैं। इन केसों को अन्ट्रेसेबल कह कर खत्म कर दिया जाता है और मामलों को छोड़ दिया जाता है। मैं कुछ सुझाव भी इस सम्बंध में देना चाहता हूं। क्लास 1 और क्लास दो की जो टाप मोस्ट एग्जेक्टिव पोस्ट्स हैं, और पुलिस में बड़ी बड़ी और छोटी छोटी नौकरियां हैं उन में हरिजनों को लिया जाना चाहिये और उनका जो कोटा है वह पूरा किया जाना चाहिये। अधिकांश हरिजन गांवों में रहते हैं। अगर इनको एक या दो एकड़ जमीन मिल जाए तो हो सकता है कि ये जो ज्यदितियां इनके साथ होती हैं, उनका वें मुकाबला कर सकें। जो सरकारी जमीन फालतू पड़ी हुई है वह इनको दी जानी चाहिये। जिन के पास पचास एकड़ से अधिक जमीन हो उन से लेकर भूमिहीन हरिजन किसान मजदूरों में वितरित कर दिया जाना चाहिये। मैं आपको अपने जिले की बात बतलाता हूं। मेरे जिले में ऐसे ऐसे पूंजीपति हैं जिन के पास पांच पांच सौ एक एक हजार एकड़ जमीन है। लेकिन दूसरी तरफ हरिजन हैं, जिन के पास एक दो बीघा भूमि भी नहीं है, यह जुल्म नहीं तो क्या है?

एक दिल्ली की बात मैं आप को सुना कर बैठ जाऊंगा। दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान बना। कांग्रेसी शासन ने इस प्लान के तहत हरिजनों को दिल्ली से निकाल बाहर फेंकने का प्लान बनाया है जैसे पहले जमाने में हुआ करता था कि जो चमार का चूहा होता था वह शहर से बाहर रहता था। इस प्लान के तहत बीस हजार झुग्गी झोंपड़ियों को डिमालिश किया गया है। उनको उठा कर जमना पार फेंक दिया गया है। उनको यहां रहने तक का हक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सारी समस्या का अध्ययन करने के लिए इसका समाधान सुझाने के लिए एक हाई पावर्ड

कमिशन की स्थापना की जाए। उस कमिशन की जो रिकोमेंडेशंज हों उनको इम्प्लेमेंट किया जाए। इसको नैशनल प्राबलम मान कर चला जाए। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई कोई भी हो हम में पोलिटिकल अवेकनिंग आ गई है और हम किसी भी प्रकार के जुल्म को बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा सरकार इसको एक नैशनल प्राबलैम मान कर और इसके हल के लिए एक हाई पावर्ड कमिशन बना कर इन्क्वायरी करे और उसके सुझाव के अनुसार अमल करे।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आज तक हम तुम्हारे जुल्म और सितम पर स्वाद करते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीस बरस हो गए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को पावर में आए हुए और राज्य चलाते हुए। पहले जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और आज श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। बीच में अठारह महीने तक लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री रहे। यह मातृत्व का प्रश्न है। इन्दिरा गांधी जी आज प्रधान मंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि वे देखें कि किस तरह से आंध्र में औरतों को नंगा कर के बइज्जत किया गया है। यह हरिजन स्त्रियों का ही प्रश्न नहीं है, सारे समाज का प्रश्न है। देश का यह प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा षडयंत्र चल रहा है। इसके पीछ फारेन मनी काम कर रहा है। मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यह जो एक बहुत बड़ा षडयंत्र चल रहा है, इसके प्रति वह सजग हों। कमिंग इवेंट्स कास्ट देअर शडो फिोर। खतरे की घंटी बज रही है। सरकार सावधान हो प्रदेश सावधान हो। अभी साधू राम जी ने कहा है कि एक चौथाई हमारी आबादी है। हम कमजोर नहीं हैं। हम मजबूत हैं और मजबूत हो कर हमें आगे बढ़ना होगा। हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा

कर बहियां बल आपनी तजौ पराई आस हम कमजोर नहीं हैं, हम मजबूत हैं। लेकिन इस में गवर्नमेंट को भी सहायता प्रदान करनी होगी। हमारे लड़के एम०ए०, बी०ए०, एल० एल० बी० पास करके गलियों में घूम रहे हैं। इंदिरा गांधी की चाहे हकूमत हो या चरण सिंह की रही हो, जनसंघ की हो या कांग्रेस की हो, उनको कोई पूछता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। जो हमारा कोटा है और जो हमारा अधिकार है, वह हमें मिलना चाहिये।

ये जो घटनायें घटी हैं, इनकी छानबीन सैंटर को करनी चाहिये। यह क्लास वार की निशानी है। सैंटर की ड्यटी है कि वह इनको इनवैस्टीगेट करे। आप रिपोर्टस मांगते हैं इन के बारे में लेकिन आपको करैक्ट रिपोर्टस नहीं आती हैं। पटवारी, चौकीदार आदि की रिपोर्टस आ जाती हैं, नीचे से ऊपर तक जो रिपोर्टस भेजी जाती हैं, वे गलत रिपोर्टस होती हैं। स्टेट्स डू नाट सैंड करेक्ट रिपोर्टस। हम आपके एलची हैं। हम आपको सही खबरें ला कर देते हैं। आंध्र में नंगा नाच हुआ है। मैं श्री मुत्याल राव से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी कांस्टिट्युएंसी में जा कर देखा है और क्या आंध्र में नंगा नाच नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारे लड़के दबाये गए हैं, उनको कुयें में फेंका गया है। यू पी में आजकल प्रजीडेंट्स रूल है, और होम मिनिस्टर जो हिन्दुस्तान के हैं, उनकी यह ड्यटी है कि देखें कि वहां ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है।

शिक्षा संस्थाएं जितनी हैं, उन के नामों के साथ ये जो मारवाड़ी आदि शब्द लगाये जाते हैं, इनको खत्म किया जाए। हमारे जो हरिजन भाई हैं अगर उन में इन शिक्षण

[श्री शिवनारायण]

संस्थाओं में छः स्थान रिजर्व होते हैं तो सातवां आदमी हमारा नहीं लिया जाता है फिर चाहे वह कितना ही कम्पीटेंट क्यों न हो। नौकरियों में हमारे लोगों को नहीं लिया जाता है। कितनी ही दरख्वास्तें दी जाती हैं लेकिन हमारे लड़कों को चपरासी तक नहीं रखा जाता है। अगर हम भी रिकोमेंड करते हैं किसी को चपड़ासी के लिए और वह हरिजन होता है तो भी नहीं रखा जाता है।

मैं चाहता हुं कि आप लैण्ड रिफार्म्ज की तरफ सब से पहले ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में यह कहा गया है कि बारह एकड़ से ज्यादा भूमि कोई नहीं रख सकता है। लेकिन वहां लोगों ने अस्सी अस्सी और नव्वे नव्वे एकड़ भूमि रख छोड़ी है। आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उन से फालतू जमीन लेकर भूमिहीनों में, हरिजनों में इसको बांट देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हल हम चलाते हैं और पैदा करके सफेदपोशों को मैं खिलाता हूं। अपने दिल पर हाथरख कर देखिये कि हमारी क्या हालत है। बरसात में खेतों की निराई हम करते हैं, सिर पर मैला हम ढोते हैं। हमारी दशा इस तरह की बनी रहे यह बहुत ही दुख की बात है।

सरदार स्वर्ण सिंह जी को हमने कहा कि मिलिटरी में हमारी रेजीमेंट रखी जाए। जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमारे साथ मजाक किया जाता है।

रेलवे डिपार्टमेंट में अधिकारी लोग रात दिन हम को गालियां देते हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं, उनको गालियां देते हैं।

मैं चाहता हूं कि ये जो सब बातें हैं, इनके बारे में आप डीपली थिंक करो। आज जरूरत इस बात की है कि हम उसी नारे को अपनायें जिस को हमने 1942 में अपनाया था यानी डू और डाई, करो या मरो। यह गांधी जी का नारा था। अगर आपने इसको अपनाया तो जो नक्शा है वह एक दिन में बदल सकता है। सरकार को इस बात में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिये।

गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है।

MR. SPEAKER: Now, there are only ten more minutes left. At least 10 minutes must be given to the hon. Minister so that he may reply to all the points raised.

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon): I want only two minutes. You have not called even one Muslim Member to speak.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): I also want to speak.

MR. SPEAKER: As Shri Thirumala Rao has already pointed, I am really surprised that not one Member either from the Opposition or from the Congress Benches has expressed at least regret on behalf of Andhra Pradesh.

SHRI ABDUL GHANI DAR: Please give me only two minutes.

MR. SPEAKER: Everybody is asking only for two minutes.....

SHRI ABDUL GHANI DAR: We have every right to speak and participate in this.

MR. SPEAKER: The other Members too have a right to speak.

SHRI ABDUL GHANI DAR: It is very sad that you are not giving us a chance. We have every right to participate.

MR. SPEAKER: There are 522 Members and not only the hon. Member. On the Congress side also there are 290 Members. Nobody has any special pri-

vilege; all have equal rights and equal privileges here; nobody has got less privileges.

I was really surprised that no Member had expressed regret for what had happened in Andhra Pradesh. It was something ghastly which had happened there and somebody should express regret at least. I would now call upon Shri Tenneti Viswanatham to speak for just two minutes.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): I rise in sorrow, I rise with great anguish of mind, and I rise also in anger at what had happened in several parts of the country and particularly in Kanchikacherla in Andhra Pradesh. I come from that State and I hang my head down in shame. I was always taking pride in the fact that having regard to the great propaganda which we had carried on during Mahatmaji's movement, these things would never happen in Andhra Pradesh. But today, as I said, I hang my head down in shame.

I am not going into the various aspects into which hon. Members have gone. These are all familiar things. In fact, the law has provided against all these things. We need not speak again what we spoke forty years ago. The law is there, but the implementation is very very defective.

Since there is no time, I shall give just two suggestions. One is that the practice of untouchability in any form should be made a cognizable offence. That is the first thing.

SHRI SONAVANE: It has been made so, but there is no implementation.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): It should be made a capital offence.

SHRI RANDHIR SINGH: There should be capital sentence for it.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: The Act is there on the statute-book. But in regard to the implementation, at the investigation stage, there is great difficulty. These Harijans belong to a poor class of society. They are not moneyed, and sometimes these crimes are committed by those who are affluent or in a affluent circumstances. Therefore, I suggest that a very fair percentage of the constabulary must be filled up by the Harijan communities and the Scheduled Caste communities. For, that is the first stage of investigation. Further, at the level of the head constables and also the sub-inspectors, there must be a greater proportion of people from these communities, because it is these people that carry on the investigation and it is these people that generally are beguiled by those who have committed the crime and who perhaps are behind these crimes.

These two things could be done without amendment of any Act. It is only a question of giving executive instructions. I want the Home Minister and the Prime Minister to consider this particular aspect and impress on the States to do this.

The first information report in the Andhra case was given almost on the same day when the boy had to run away about a hundred yards after falling down from the pole in a bruised or burnt condition. Within less than two hours, I suppose the report was there. But for weeks and weeks no arrest was made. These delays can happen only under two circumstances, namely if there is money behind or if there is politics behind. I understand that in this particular case both the things were there. I want the Home Minister to exercise all the care he can and all the influence that he has at his command to bring out the culprits so that this may be an example throughout the country to show that he social conscience of the people has been stirred now as on no other occasion. Let us dedicate ourselves from today to root out this untouchability in every form in action.

MR. SPEAKER: The Home Minister.

श्री अबदुल गनी डार : "किस किस तरह सताते हैं ये बुत हमें निज़ाम, हम ऐसे हैं कि जैसे किसी का खुदा न हो।" मैं वाक आउट करता हूं।

[شری عبدالغنی ڈار ۰۰کس کس
طرح ستاتے ھیں یہ بت ھمیں
نظام - ھم ایسے ھیں کہ جیسے کسی کا
خدا نہ ھو۔۰۰ میں واک آوٹ کرتا ھوں-]

Shri Abdul Ghani Dar then left the House.

श्री किकर सिंह : (भटिंडा) : स्पीकर साहब मैंने कालिंग एटेन्शन नोटिस दिया है। मुझे भी दो मिनट जरूर मिलने चाहिए। होम मिनिस्टर साहब तो रोज स्पीचें करते रहते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है। हमारे लिए यह बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): As regards the incident which gave rise to this discussion, I would like to give certain facts. When I made my statement yesterday, I had said that 6 out of the 7 accused were already arrested. According to a message which I just received while sitting here, the one remaining who was absconding, was also arrested on the night of the 2nd at Raichur. This is as regards the point made by the speaker who preceded me as to whether investigation was started immediately. But the explanation I got from the Andhra Pradesh Government was that most of these people had left that place and they were spread all over the State; one was even outside the State. They immediately started the investigation, but naturally it took time to get hold of these people. As I said, the seventh accused was arrested at a distant place, Raichur.

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एफ० आई० आर० लाज करने के बाद जब काग्नीजेंस लिया गया और एक्यूज्ड एब्सकांड कर रहे थे, तो उस दरमियान में दफा ८८ और ८९, सी आर० पी० सी० के तहत एक्यूज्ड के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

MR. SPEAKER: He is not yielding. He cannot cross-examine him like that.

SHRI Y. B. CHAVAN: Let me complete my sentence. He cannot ask me questions at every stage.

18.57 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

As regards the other incident about which I made a statement yetserday about naked women being paraded, they certainly made certain investigation trying to find out information. But this information is not found to be correct and they have issued a contradiction about it.

Hon. Members also have mentioned certain facts. The Communist Party Member referred to some telegram which he has received about some incident in the same district in the same State. Naturally, I will have to go into the details and get a report from the State Government before I can give a reply.

I entirely agree that it is not enough that we have some sort of philosophy, but not the machinery to implement it. This country has accepted equality of citizenship before the law and removal of untouchability has been accepted as a fundamental principle of our Constitution and we have also passed laws making untouchability a cognisable offence, but it is not enough to have laws, it is not enough to merely have a Constitution, it is not enough to have only the philosophy. Now it is time we implemented it. That is, really speaking, the crying need of the hour and we have to think about now we do it.

I must say in this matter that most of the States are doing it, but certainly social conditions are still the same. Unfortunately, this feudal atmosphere in the villages even in this democracy is not yet changed. Psychological and social conditions naturally need to be changed and changed fundamentally. For that matter, the instrument of law and the instrument of Government has

to be used, used very vigorously and honestly. I entirely agree there.

As regards the economic programme, it is the policy practically of all parties and all governments to give priority to the problems of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I think an honest effort has been made by this Government also. I am not here just to defend what Government have done or are not doing. Certainly in what we are doing, we are doing our duty, and what we are not doing is our failure. We must accept that sort of attitude in this matter.

There were two or three suggestions. We will have to take it up at the highest level of the Chief Ministers in a conference and try to emphasise the necessity of being more alert. These are continuing problems. It is not enough that we are alert once; it is a question where we have to be alert continuously and constantly. Constant vigilance is necessary.

19 hrs.

I am thinking of meeting the Chief Ministers to discuss some of the problems. I will give priority to this problem and discuss it with them when I meet them.

As regards the general question of the problems of Scheduled Castes and their reservation in services and other economic problems, as we know, the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is supposed to look into it. We have found that the implementation of that policy is the main problem. The Minister of Social Welfare is considering the suggestion whether there should be a parliamentary committee to go into this problem.... (*Interruptions.*)

AN HON. MEMBER: It was promised but denied.

SHRI Y. B. CHAVAN: He has not promised. But as I say, he is considering the suggestion. I have been discussing this matter with him even before I got up here now. I shall discuss this matter with him. If not a parliamentary committee, whatever other committee he may have, in mind he will consider it..... (*Interruptions.*)

AN HON. MEMBER: No other committee.

SHRI Y. B. CHAVAN: Well, you have said it now.

श्री मोहन प्रकाश : नौकरियों में रखने के लिए नहीं लेकिन जो नौकरियों में लगे हुए हैं उन के कैरेक्टर रोल खराब कर के उन को निकाल दिया जाता है (व्यवधान) . . .

SHRI Y. B. CHAVAN: The suggestion to have a parliamentary committee is there. Government has no doubt that if there is some sort of a committee—even if it is not a parliamentary committee—it will go a long way and it is necessary to create an atmosphere so that the administration at all levels will feel that the highest body is watching their performance. This is the basic principle behind it and I am sure the Minister of Social Welfare will certainly take this into consideration. I do not want to repeat whatever everybody has said; I am not replying to this debate in a spirit of replying. I am really-speaking, speaking in the spirit of endorsing it. That is all that I have to say.

19.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 5, 1968/Chaitra 16, 1890 (Saka).

GMGIPND—LS—II—157 (Ai) LSD—4-10-68—1010.